

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या **5248-5274/2017**

[2017] 3 एस. सी. आर 529

फलों और सब्जियों के लिए विशेष कृषि उत्पाद बाजार समिति...अपीलार्थीगण

बनाम

एन. कृष्णप्पा और अन्य ईटीसी

...प्रतिवादीगण

निर्णय

रंजन गोगोई.....न्यायाधिपति

नवीन सिन्हा.....न्यायाधिपति

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 - धारा 4 (1), 6 (1)-भूमि मालिकों द्वारा
चुनौती दिए गए अपीलार्थी के विपणन यार्ड के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण
के लिए अधिसूचना- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित
किया कि अधिग्रहण वैधानिक गैर-अनुपालन से ग्रस्त है, हालांकि, इसमें शामिल

जनहित को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही को दरकिनार करने के बजाय उसने अधिसूचना की तारीख को स्थानांतरित कर दिया धारा 4 (1) के तहत । मुआवजे के निर्धारण के लिए-भूमि मालिकों और अपीलार्थी की अपीलों में, एकल न्यायाधीश के साथ सहमति जताते हुए खंड पीठ ने अधिग्रहण के व्यापक सार्वजनिक महत्व को देखते हुए अधिग्रहण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अधिग्रहण में शामिल व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013, धारा 24(2) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी बनाम बारंगोर जूट कारखाना और अन्य। (2005) 13 एससीसी 477:[2005] 5 पूरक एस. सी. आर. 421 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 5 पूरक।एससीआर 421 उस पर भरोसा करें पैरा 9

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : 2017 की सिविल अपील संख्या 5248 -5274।

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. ए. सं. 5-8,33-34,35-

40,41,45,5247-51,47,48,5214-16,2011 के 49 और 5261 और 2011 के आर.

पी. सं. 302 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी. ए. संख्या 5275-5278, 5279-5287/2017

डॉ. राजीव धवन, वी. लक्ष्मी नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता।, डॉ. नंदा किशोर, निशांत पाटिल, अविनाश कुमार मिश्रा, शांता कुमार महाले, जी. डी. अश्वथा नारायण, अमित जे., वी. एन. रघुपति, अनूप जैन, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति... नवीन सिन्हा

1. अनुमति दे दी गई।

2. इन अपीलों में विवाद अपीलार्थी के विपणन यार्ड के विस्तार के लिए गाँव गोलीमंगला, सरजापुर होबली, आंचल तालुक, जिला बेंगलोर में 42 एकड़ 32 गुंटा भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। अधिग्रहण की कार्यवाही में खामियों को देखते हुए, लेकिन बड़े सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण को रद्द करने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को मुआवजे के निर्धारण के लिए अपने आदेश की तारीख यानी 22.11.2010 पर स्थानांतरित कर दिया। आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी और भूमि मालिक दोनों इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत वैधानिक अधिसूचना 20.5.2002 पर प्रकाशित की गई थी और पंचाट 31.01.2005 पर दिया गया था। भूमि मालिकों द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने

मूल अधिग्रहण अभिलेखों को देखने के बाद कहा कि अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत प्रकाशन की अंतिम तिथि से वैधानिक समय के भीतर की गई थी। लेकिन अधिग्रहण को अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में वैधानिक गैर-अनुपालन और अधिनियम की धारा 5 ए के तहत आपत्तियों पर अनुचित विचार का सामना करना पड़ा। अधिग्रहण के सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही को हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया और इसके बजाय, धारा 4 (1) अधिसूचना की तारीख को स्थानांतरित करके सक्षम प्राधिकरण बनाम बारंगोर जूट फैक्ट्री और अन्य, (2005) 13 एस. सी. सी. 477 पर भरोसा करते हुए राहत को ढाला गया।

4. भूमि मालिकों और अपीलार्थी दोनों द्वारा अपीलों को प्राथमिकता दी गई। डिवीजन बेंच ने मूल रिकॉर्ड को नए सिरे से तलब किया। यह आदेश के पैराग्राफ 40 में चर्चा किए गए कारणों के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा वैधानिक समय के भीतर नहीं थी। लेकिन, अधिग्रहण की कार्यवाही में हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए, यह अधिग्रहण के व्यापक सार्वजनिक महत्व के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बताए गए तर्क से सहमत था।

5. अपीलकर्ता-बाजार समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने आग्रह किया कि मूल अभिलेखों से विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष कि अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा एक वर्ष के वैधानिक समय के भीतर की गई थी, सही था और खंड पीठ द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। गाँव की चावड़ी में धारा 4 (1) के तहत प्रकाशन की अंतिम तिथि 05.08.2002 थी। 02.08.2003 पर धारा 6 (1) के तहत की गई घोषणा समय के भीतर थी। अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना की तारीख को किए गए तरीके से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था।

6. कर्नाटक राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण में शामिल व्यापक सार्वजनिक हित के साथ-साथ भूमि मालिकों के हित को ध्यान में रखते हुए धारा 4 (1) अधिसूचना की तारीख को सही ढंग से स्थानांतरित कर दिया।

7. भूमि मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि एक बार डिवीजन बेंच के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत घोषणा वैधानिक समय से परे थी, अधिग्रहण की कार्यवाही को बनाए नहीं रखा जा सकता था। इसके प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आज तक न तो कब्जा लिया गया है और न ही भूमि मालिकों को मुआवजा दिया गया है। इसलिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (जिसे इसके बाद '2013 अधिनियम' के रूप में

संदर्भित किया गया है) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही भी समाप्त हो गई।

8. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। मूल अधिग्रहण रिकॉर्ड भी हमारे द्वारा तलब किए गए थे। डिवीजन बेंच की टिप्पणियां उचित प्रतीत होती हैं। लेकिन अधिग्रहण में शामिल व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए राहत को ढालते हुए पारित आदेश की प्रकृति में, और बारंगोर जूट फैक्ट्री (उपरोक्त) को देखते हुए, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

9. बारंगोर जूट फैक्ट्री (ऊपर) में अधिग्रहण को वैधानिक गैर-अनुपालन का सामना करना पड़ा। अधिग्रहण में शामिल व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, अधिग्रहण को अलग रखने से इनकार करते हुए राहत को न्याय के हित में ढाला गया था:

“14..... इस स्तर पर विवादित अधिसूचना को रद्द करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम बेपरवाह नहीं हो सकते कानूनी स्थिति कि अधिग्रहण करने वाला प्राधिकारी विवादित अधिसूचना रद्द होने की स्थिति में भूमि अधिग्रहण के लिए हमेशा एक नई अधिसूचना जारी कर सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि भूमि की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए भूमि मालिकों को देय मुआवजे की राशि अधिक हो सकती है। इसलिए, अंतिम प्रश्न भूमि मालिकों को देय मुआवजे की मात्रा के बारे में होगा। इस स्तर पर

अधिसूचना को रद्द करने से कई कठिनाइयाँ और व्यावहारिक समस्याएं पैदा होंगी। विवादित अधिसूचना को रद्द करने में शामिल समस्याओं के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को संतुलित करते हुए, हमारा विचार है कि भूमि मालिकों, यानी रिट याचिकाकर्ताओं को उचित रूप से क्षतिपूर्ति करने का एक बेहतर तरीका होगा, जिससे वे वंचित हैं। न्याय के हित हमें इस कार्यवाही को अपनाने के लिए राजी करते हैं।

10. चूँकि 2013 के अधिनियम के संबंध में विवाद के लिए उचित अवसर के साथ तथ्यों की जांच की आवश्यकता होगी, इसलिए हम वर्तमान कार्यवाही में इससे निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं और पीड़ितों के लिए उचित मंच के समक्ष कानून के अनुसार अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं, यदि ऐसी सलाह दी जाती है।

11. इसलिए सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

बेंच

रंजन गोगोईन्यायाधिपति

नवीन सिन्हान्यायाधिपति

नई दिल्ली

निर्णय की तारीख अप्रैल 17,2017

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा